चीनी मिलों को मिलेगा 7,200 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। चीनी मिलों को केंद्र सरकार से भी राहत पैकेज मिलने का इंतजाम हो गया है। प्रधानमंत्री की ओर से गठित केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने चीनी उद्योग को 7,200 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त के कर्ज समेत कई रियायतों की सिफारिश की है। इस रकम का इस्तेमाल गन्ने की बकाया रकम के भुगतान के लिए किया जाएगा मिलों की अधिकांश मांगे केंद्र ने मान ली हैं लेकिन गन्ने के भाव का मुद्दा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। जीओएम की इन सिफारिशों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

शुक्रवार को गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि चीनी मिलों को तीन साल की एक्साइज ड्यूटी, सेस और सरचार्ज के बराबर बैंकों से कर्ज मिलेगा, जिसका 12 फीसदी ब्याज माफ होगा। लेकिन इस कर्ज का इस्तेमाल गन्ना किसानों के भुगतान के लिए ही करना पड़ेगा। ब्याज माफी में से 7 फीसदी शुगर डेवलपमेंट फंड से आएगा जबकि 5 फीसदी ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। इस तरह मिलने वाला कुल 7,200 करोड़ रुपये का कर्ज मिलों को 5 साल में चुकाना होगा, जिसमें शुरू के दो साल अदायगी से छूट दी जाएगी। सरकार चीनी मिलों के मौजूदा कर्ज के पुनर्गठन पर भी राजी हो गई है। मंत्रियों की समिति ने पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की सीमा 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने और प्रति वर्ष 40 लाख टन रॉ शुगर के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है। हालांकि, चीनी के आयात पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगा है। पवार का कहना है कि गत जुलाई से ओपन जनरल लाइसेंस के तहत चीनी का आयात नहीं हुआ है, लेकिन इस पर नजर रखी जाएगी।

बकाया चुकाने में होगी आसानी: इस्मा

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे चीनी उद्योगों को वित्तीय संकट का मुकाबला करने और किसानों का बकाया भुगतान देने में मदद मिलेगी। समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए लाभकारी, तर्कसंगत और पारदर्शी फार्मूला लागू करना जरूरी है।

गन्ने का भाव राज्यों के भरोसे

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों की मुराद भले ही पूरी कर दी हो, लेकिन गन्ने के भाव का मुद्दा राज्यों पर डाल दिया है। कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि गन्ने के भाव का फार्मूला तय करने के लिए राज्यों को एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश पहले ही इस तरह की समिति बनाने का ऐलान कर चुके हैं। गन्ना मूल्य के लिए राज्य आमदनी बंटवारे के तरीकों पर विचार कर सकते हैं।

किसानों-मिलों दोनों को हो लाभ : अखिलेश

नई दिल्ली। चीनी के मसले पर कृषि मंत्री शरद पवार की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कभी किसानों का नुकसान नहीं कर सकती। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को मदद और चीनी मिल मालिकों को रियायत दे रही है। हम चाहते है कि गन्ना किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिले और चीनी मिले भी चलती रहें। वहीं सपा नेता नरेश अग्रवाल ने मांग की कि केंद्र सरकार को गन्ना किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी चाहिए। गौरतलब है कि कई दिनों से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कृषि मंत्री शरद पवार की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल थे। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के कदमों से प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्याएं सुलझेंगी।

Amar Ujala
7/12/13